



BHARTIYA SWARNIM YUG PARTY

भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी

न्याय * साम्या * सदृश्वेक

भारतीय स्वर्णिम
युग पार्टी
का
घोषणा पत्र
प्रथम-संरक्षण 2020-21



विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम (म.प्र.) 457001 Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Rattlam (M.P.) 457001

8989-00-1929



www.bsyparty.com



info@bsyparty.com



[bsy.party](https://www.facebook.com/bsy.party)



[@bsy_party](https://twitter.com/bsy_party)



[bsy party](https://www.youtube.com/bsy party)



घोषणा पत्र / प्रयास पत्र

परिचय

- भारतीय** : सम्पूर्ण रूप से भारतीय जीवन—दर्शन पर आधारित दल जो कि हर भारतीय के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए कर्मशील रहेगा।
- स्वर्णिम** : एक स्वर्णिम अर्थात् परिपूर्ण व समृद्ध जीवन सबका अधिकार है। सबके पूर्ण रूप से सुखी, स्वस्थ व शांतिमय जीवन की कामना करते हुए प्रयासरत रहना हमारा ध्येय रहेगा।
- युग** : 2020 के बाद का कालखण्ड वर्तमान समय से ही उस युग में प्रवेश चुका है जबकि एक नए दौर में हमें अधिक बौद्धिकता से गुणवत्तामय जीवन — शैली का चयन करना होगा। अनावश्यकता का त्याग करते हुए, सार्थकता का वरण करते हुए ही हम इस नए युग में उत्कृष्ट जीवन शैली पा सकेंगे। हम इसी अवधारणा पर आगे बढ़ेंगे।
- पार्टी** : अन्य पार्टियों से पृथक यह पार्टी दूरदर्शिता एवं भविष्य की सुरक्षा के साथ वर्तमान में निश्चित कार्ययोजना के साथ सर्वजन हिताय एवं जीवन की प्रतिबद्धता के साथ अनवरत कल्याण पथ पर अग्रसर है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- प्राकृतिक न्याय** : आज हम प्रकृति के मूल तत्व को भूल गए हैं। हमें पुनः प्राकृतिक स्त्रोत की ओर मुड़ना होगा। प्राकृतिक न्याय अर्थात् पर्यावरण और प्राणीमात्र के प्रति जागरुक और संवेदनशील होना होगा तभी हम सबका अस्तित्व रहेगा अर्थात् जियो और जीने दो।
- न्याय** : हर मानव को न्याय मिले, न्याय आधारित व्यवस्था में सबको जीने व विकास करने की स्वतंत्रता हो।
- साम्या** : लिंग, वर्ण, रंग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर प्रत्येक को साम्या यानि समानता की दृष्टि से जाना देखा, समझा जाए। कहीं कोई भेद न हो।
- सद्विवेक** : सद्विवेक के लिए शिक्षा में नैतिकता के साथ जीवन—मूल्यों और आध्यात्मिकता का समावेश हो।

- विश्व बंधुत्व** : एक व्यवस्था में सभी राष्ट्रों का जब तक सूत्रीकरण न होगा, तब तक विश्व में अशांति, तनाव व अराजकता रहेगी। विश्व नागरिकता का ध्येय ही इसका समाधान है। युद्ध में लगने वाला, हथियारों में खर्च धन बचाकर मानव कल्याण में लगाने के लिए विश्व में बंधुत्व का प्रचार—प्रसार हमारा लक्ष्य है।

नारी का सम्मान :

नारी के सम्मान के लिए:

1. हमे भ्रूण हत्या रोकनी होगी ।
2. बालिका शिक्षा अनिवार्य करनी होगी ।
3. बाल—विवाह पर रोक लगे ।
4. विधवा विवाह को समर्थन मिले
5. बहु—विवाह पर रोक ।
6. पर्दा—प्रथा, घूंघट—प्रथा एक दायरे में सीमित हो ।
7. सती—प्रथा का उन्मूलन ।
8. छेड़छाड़ व बलात्कार के विरुद्ध कड़े कानून ।
9. घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा व अंधे विश्वास से ग्रस्त स्त्री शोषण का विरोध हो ।
10. अवसर, कार्य—व्यवसाय आदि में स्त्री स्वतंत्रता व समानता पर जोर ।

शोषण का विरोध : बालश्रम, ग़रीबों का शोषण, बेगार प्रथा आदि के विरुद्ध संघर्ष ।

जनता : जनता के हर हक् के लिए उठेगा हमारा कदम ।

कल्याण : लोक—कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारा आदर्श है । समाज—कल्याण के लिए हम सदैव समर्पित हैं ।

भारतीय संविधान : भारत के सविधान में पूर्ण आस्था के साथ, उसके हर तथ्य नियम का पालन व कर्म—संहिता पर अनुगमन हमारा उद्देश्य है ।

समाजवाद : पूंजीवाद की बढ़ती रफ्तार को थामते हुए समाजवाद के साथ एक साम्य, संतुलन को साधना ।

पंथ निरपेक्षता : पंथ निरपेक्षता में ही “हर धर्म” का मान—सम्मान है । हृदय से तभी कोई संघर्ष न होगा । सबके मूल में एक भाव को प्रकाश लाएगा ।

लोकतंत्र: लोकतंत्र ही विकल्प है हर तरह की तानाशाही और अन्यायवादी व्यवस्था का आदर्श प्रत्युत्तर है लोकतंत्र ।

सम्प्रभुता : भारतीय सम्प्रभुता हमारी प्राथमिकता है । भारत की सम्प्रभुता हर राष्ट्र के लिए आदर्श व मिसाल है ।

शक्त्रीय एकता व अखण्डता : धर्म, जाति, क्षेत्र वर्ग, भाषा और किसी भी प्रकार की विविधता के स्वागत के साथ हम सम्प्रदायिकता व राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता में विश्वास व्यक्त करते हैं । पार्टी हर पंथ व भिन्नता के मध्य सौहार्द के संतुलन की तरह सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है ।

अहिंसा : हम अहिंसक भाव से सम्पूर्ण लोकमंगल की कामना करते हैं। जीव व प्राणी—मात्र के लिए हमारी संवेदनशीलता प्राथमिकता में सदैव रहेगी। यथासंभव प्रत्येक जन और जंतु के लिए हम इसी भाव से तत्पर रहेंगे।

निर्धनता : अनादि समय से अमीर—ग़रीब के अंतराल का बढ़ते जाना सबके समक्ष है। निर्धनता का उन्मूलन हमारा मिशन है। अवसरों में ग़रीबों का स्थान पहले होना चाहिए।

असहायता : निःशक्त और असहाय लोगों के लिए हम सरल बन सकें, यह हमारा प्रयास और मंतव्य सदैव रहेगा। कैसे असहाय का उत्थान हो, हमारा यही चिंतन रहेगा।

दलित : आज भी दलित उपेक्षित और पीड़ित हैं। उनका शोषण हो रहा है, अब यह बंद हो। समानता के साथ मुख्यधारा में उनका स्वागत हो।

दिव्यांग : यद्यपि दिव्यांगों के लिए शासन / प्रशासन में कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास दिव्यांग के लिए त्वरित और तत्पर सेवा का होगा।

तृतीय लिंग : थर्ड जनरेशन की स्वीकार्यता कानूनन तो हो गई लेकिन समाज के मन में यह सम्मान स्वीकृत हो, इसके लिए बड़े स्तर पर कार्य की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यक : अल्पसंख्यक का भेद मिट जाता है, जब बात भारतीयता व मानवता की होती है। हमें भी भेदभाव को समाप्त करना होगा।

पिछड़ा वर्ग : वास्तव में पिछड़े वर्ग की पड़ताल और अंतिम पंक्ति के आखरी व्यक्ति तक पहुँच होनी चाहिए। कोई पिछड़ा होना ही नहीं चाहिए। यदि हम सभ्य व सुनिश्चित समाज में हैं, तो पिछड़ेपन की अवधारणा तो होनी ही नहीं चाहिए।

समता पूर्ण समाज की स्थापना : हम समतापूर्ण समाज उसे कहेंगे, जहां धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के प्रति कोई विद्वेष न हो और सबसे अहम जीने और स्वतंत्रता तथा समृद्धि में भी कोई संघर्ष न हो। यही तो समाज का वास्तविक रूप भी है, हमारे लिए हर धर्म जाति, वर्ग व भाषा का समाज समान व सम्मानीय है। सबकी पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा व पुनर्जागरण के लिए हम सब साथ—साथ हैं।

हमारी कार्य-संहिता

1. हर अन्याय का हम विरोध करेंगे।
2. हर अवैध वसूली उजागर की जाएगी।
3. रिश्वत खोरी बेनकाब की जाएगी।
4. फर्जीवाड़ा बन्द किया जाएगा।
5. भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष होगा।
6. सभी कार्यालयों के दस्तावेज औचित्यता के आधार पर आवश्यकतानुसार सार्वजनिक हो, ताकि भ्रष्टाचार की संभावना न रहे।
7. हमारी लड़ाई हर भारतीय की होगी।
8. हमारा कार्य राष्ट्र और संविधान के अनुरूप पूर्णतः मानवीय होगा।
9. हमारी सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण की होकर प्रगतिशील होगी।
10. हम हमेशा संहिताबद्ध रहेंगे।
11. समाज के अंतिम व्यक्तियों को अग्रिम पंक्ति में लाएंगे।
12. कोई भी निम्न दर्ज पर न रहेगा।
13. ऐसा हमारा प्रयास होगा, आदर्श बिजली उपभोक्ता कानून को लागू कराएंगे। विद्युत बिलों का भार न्यूनतम करवाएं।
14. लम्बित न्यायिक फैसले व प्रकरण लोक अदालत जनसुनवाई व विशेष आधार पर सुलझाये जाने की मांग करेंगे।
15. लोकपाल अधिनियम के तहत कार्य प्रगति पर पूर्णतः जोर दिया जाएगा।
16. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादा के साथ दी जाएगी।
17. हर अवैध कार्य का विरोध और वैधता पर जोर दिया जाएगा।
18. सूचना के अधिकार के साथ पारदर्शिता राष्ट्रीय एवं सुरक्षा के मामलों को ध्यान में रखकर कार्यवाही जाएगी।
19. किसी प्रतिभा के साथ शोषण नहीं हो। प्रतिभाओं को आगे आने का समानता से अवसर मिलें।
20. अपराध मुक्त परिवेश की स्थापना।
21. भ्रूण-हत्या पर रोक के कानून की पूर्णतः कार्यवाही को सुनिश्चित करना।
22. पशुओं के अवैध शिकार पर रोक लगे।
23. उपभोक्ता अधिकार को सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण चिन्तन के विषय

हम विश्व के सभी चिंतकों के सार्थक चिंतन के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, चिंतन का सार्थक सार नवनीत स्वरूप हम आत्मसात करेंगे।

धनतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र



आज धनतंत्र के बोलबाले से सब परिचित है, परदे के पीछे इसकी ताकत सक्रिय है। अगर आज हम इसके विरुद्ध खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र भी पराजित हो जाएगा। धनतंत्र लोकतंत्र को खरीदने में आमादा है।

हमारे संविधान में राजनैतिक परिदृष्टि के जो सपने देखे थे उसमें सबका साथ सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन कर सम्पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए किन्तु विधान सभा के पिछले चुनाव में सुप्रसिद्ध राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा झूटे वादे, खोखले दावे, छलीय घोषणाओं का सहारा लेने के अलावा बैहिसाब पैसा खर्च कर मतदाता भाइयों के बीच शराब, नोट, साड़ियां, कम्बल इत्यादि बांटे गए। इस चकाचोंध-शोर शराबे में आम मतदाता भ्रमित हुआ और निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले राजनैतिक प्रत्याशियों को अगले पांच वर्ष तक जनधन की लूट करने का अधिकार सौंप दिया।

हमारा संविधान तो मानवतावादी, समाजवादी लोकतंत्र का सपना देखता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना को प्रेरित करता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही राजनैतिक दलों ने राजा महाराजाओं,

इलाकेदार, माफिया तथा अपराधियों का सहारा लेकर सत्ता में आए जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र इनकी तिजोरियों में कैद होता चला गया जिसमें केवल उन्हीं नागरिकों को भागीदारी मिल सकती है जो चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च कर सके। विधान सभा तथा लोकसभा में संविधान की शपथ खाकर इन राजनैतिक पूंजीपतियों ने हमारे देश का भला नहीं किया इस कारण सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई जिसके कारण लोकतंत्र की भलाई, प्रगति, कल्याण व विकास के मुद्दे हमारी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। हमारे देश की सब समस्याओं की जड़ नेता दल व वर्तमान व्यवस्था है।

अतः भारत के राजनैतिक पटल से कचरा साफ करने के लिए साफ सुधरे प्रत्याशियों की चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों की डगमगा रही आस्था भी स्थापित करने के लिए, हमारे-आप जैसे किसी भी दलों अथवा बिना दल के ही समाज सेवा में सक्रिय जागरूक साथियों को एक साथ बैठकर सम्मेलन के माध्यम से चिन्तन करना समय की मांग है।

अतः शुद्ध पवित्र मन से निर्वाचन आयोग की विफलता तथा चुनाव में भारी मात्रा में किए गए काले धन का विश्लेषण करने एवं साफ-सुधरे लोकतंत्र के लिए नीति तैयार करने हेतु यह चिन्तन भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी भवन में आयोजित किया गया है जिसमें सभी दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों के अलावा प्रमुख समाजसेवियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं।

अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है

अगर हमारे देश में दुनिया के शीर्षक धनिक व्यक्ति शुमार हैं तो फिर देश में आर्थिक संकट क्यों है? 10 प्रतिशत लोगों के पास 90 प्रतिशत देश का धन है। यह सम्पत्ति की असमानता कब से अब तक यू ही कायम है और भविष्य में यथास्थिति बने रहे, क्यों? 90 प्रतिशत संर्ध व गुलामी की मानसिकता क्यों रहे। हम इस बढ़ती विष वृक्ष परम्परा पर अमरबेल को नष्ट करने का समय आ गया है। कार्ल मार्क्स की सच्ची सोच क्यों फिजूल जा रही है जिन्होंने कहा था धर्म जनता के लिए नशीली अफीम की तरह है जिसका इस्तेमाल पुंजीपति अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए करते आ रहे हैं। हमारी कोशिशें रहेंगी कि मार्क्स की इसी चेतावनी का उपयोग शोषित हो रही जनता को बचाने के लिए करें। रामराज में लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप की समाजवादी, समानता आदर्श तुलना है। यही हमारा ध्येय है, धन वितरण और आय की असमानता में संतुलन बनाने का प्रयास ही हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले जो पहले से ही



वितरित था उसे छिनने से रोकना होगा और पूर्वाग्रह की सोच खत्म करना होगी। आज आय छिनने की हो रही कवायद को भी रोकना होगा। असमानता का मुद्दा था ही अब तो आय और संभावना समाप्त करने की साजिश हो रही है। शोध से पता चलता है धन वितरण और आय असमानता कि अधिक असमानता विकास की अवधि में बाधा डालती है, आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है। आर्थिक असमानता कभी-कभी आय असमानता, धन असमानता, या धन अंतर को संदर्भित करती है। निजीकरण और आय की असमानता के चलते संपत्ति- धन के वितरण की असमानता में वृद्धि हुई है।

क्या है इस असमानता के कारण?

- सुधारों ने मुख्य रूप से उनकी आय में वृद्धि की है जो पहले से ही समृद्ध थे।

शोध से पता चलता है धन वितरण और आय असमानता कि अधिक असमानता विकास की अवधि में बाधा डालती है, आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है। आर्थिक असमानता कभी-कभी आय असमानता, धन असमानता, या धन अंतर को संदर्भित करती है। निजीकरण और आय की असमानता के चलते संपत्ति- धन के वितरण की असमानता में वृद्धि हुई है।

क्या हैं इस असमानता के कारण?

- सुधारों ने मुख्य रूप से उनकी आय में वृद्धि की है जो पहले से ही समृद्ध थे।
- बढ़ते निजीकरण के कारण सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार लोगों को पारिश्रमिक नहीं मिला है।
- कृषि सुधार और भूमि सुधार को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है।
- धन का पुर्ण वितरण संभव नहीं हो पाया है।
- महिलाओं को प्रायः किसान नहीं माना जाता और न ही उनके पास कोई भूमि है, इसलिए किसानों के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है।
- भारत में पुश्टैनी अरबपतियों की संख्या अधिक है और ऐसे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धन का हस्तांतरण एवं संचयन होता रहता है।
- रोजगार में कमी का भी आय असमानता पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। - राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की जुगत में प्रायः सरकारें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की अनदेखी करती हैं।

बेरोजगार बन्धुआ मज़दूर

कोई भी बेरोजगार न रहे, बंधुआ नहीं उन्मुक्त और स्वतंत्र व मर्यादित असीमित रोजगार की संभावना सृजित की जाए। मज़दूर हो या किसान सबका समान हक हो। हाथ खाली कहाँ हैं, जो बेरोजगारी की चर्चा करें

आंखों के आगे एक तस्वीर उभरती है कि अपने देश में शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। बेरोजगारी का ये विकराल रूप आर्थिक मंदी का ही एक संकेत है। देश की तस्वीर बनाइए तो नजर आयेगा कि हम लोग भीतर से खोलते हुए एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं जो किसी भी क्षण फट सकता है। शिक्षित युवाओं की कुल तादाद का छठा हिस्सा बेरोजगारी के चंगुल में है और, लगभग 1 करोड़ की संख्या में मौजूद बेरोजगारों की तादाद में हम सालाना 1 करोड़ ऐसे युवाओं की तादाद और जोड़ रहे हैं जो उच्च शिक्षा के संस्थानों से कोई ना कोई डिग्री लेकर निकलते हैं। रोजगार की तलाश करते इन युवाओं में महिलाओं की संख्या अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है।



साथ में, ये भी सोचिए कि इन युवजन को एक तो रोजगार हासिल नहीं है दूसरे इनमें ज्यादातर को ऐसा हुनर भी हासिल नहीं कि जो उनको रोजगार के काबिल माना जा सके।

बेरोजगारी के इस उभरते हुए मंजर में जरा अब आर्थिक मंदी के रंग चढ़ाकर देखिए और आप साफ दिखेगा कि देश एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है जो कभी फट सकता है नये ग्रेजुएट्स को नौकरी पर रखने की बात कौन कहें यहां तो आलम ये है कि कंपनियां अपने मौजूदा कर्मचारियों की छंटनी करने पर लगी हैं। सो, स्नातक की डिग्री लेकर निकले, हुनर से खाली मगर महत्वाकांक्षा से भरे हमारे ये नये-नवेले एक ऐसे बाज़ार में खड़े हैं जहां उनका स्वागत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं।

निजी जानकारियों की गोपनीयता और सुरक्षा

गोपनीयता और निजता के लिहाज से ये चिंता का विषय है। जो सरकारें लोगों और उनकी निजी जानकारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जमा करना चाहती है उनके लिए इस तरह के अनेकों उपकरण उपलब्ध हो जाते हैं। डाटा सुरक्षा के अभाव में इतने लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां दांव पर लगी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग में फर्जीवाड़ा होने की घटनाओं में हालिया वर्षों में तेजी आई है। इन घटनाओं का असर इंटरनेट के उपभोग की विश्वसनीयता पर पड़ रहा है।

इसके अलावा चुनाव और नीति निर्धारण के संदर्भ में सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा भी इस प्रकार के डाटा में रुचि दिखाई जाती है। इसलिए डाटा संरक्षण को वैधानिकता प्रदान करना जरूरी हो चला है। हालांकि कई विशेषज्ञ डाटा संरक्षण विधेयक को दोधारी तलवार की संज्ञा दे रहे हैं, जिसमें एक तो भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखने की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर यह केंद्र सरकार को रियायत देकर नागरिकों की निगरानी करने की मंजूरी देता है। निजी जीवन का सम्मान, समानता और स्वतंत्रता की वास्तविकता है, हमारी जानकारीयों का व्यापार बन्द हो, सबकी सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुनः परिभाषित करना होगा, गोपनीयता का उल्लंघन दण्डनीय अपराध हो और न्याय में पुनः आस्था बढ़े। हर नागरिक की सुरक्षा की ग्यारन्टी हो।

गोपनीयता और निजता के लिहाज से ये चिंता का विषय है। जो सरकारें लोगों और उनकी निजी जानकारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जमा करना चाहती है उनके लिए इस तरह के अनेकों उपकरण उपलब्ध हो जाते हैं। डाटा सुरक्षा के अभाव में इतने लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां दांव पर लगी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग में फर्जीवाड़ा होने की घटनाओं में हालिया वर्षों में तेजी आई है। इन घटनाओं का असर इंटरनेट के उपभोग की विश्वसनीयता पर पड़ रहा है।



इसके अलावा चुनाव और नीति-निर्धारण के संदर्भ में सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा भी इस प्रकार के डाटा में रुचि दिखाई जाती है। इसलिए डाटा संरक्षण को वैधानिकता प्रदान करना जरूरी हो चला है। हालांकि कई विशेषज्ञ डाटा संरक्षण विधेयक को दोधारी तलवार की संज्ञा दे रहे हैं, जिसमें एक तो भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखने की बात की गई है, वहाँ दूसरी ओर यह केंद्र सरकार को रियायत देकर नागरिकों की निगरानी करने की मंजूरी देता है।

रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की प्राप्ति सुलभ हो



आज के युग में मनुष्य की आवश्यकताओं में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले जीवन की तीन आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान माने जाते थे। लेकिन अब शिक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र सरकारी प्रयासों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए समाज की समुदाय की सहभागिता भी जरूरी हैं।

रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जिस देश में ये सुलभ है, वे देश विकसित है।

जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो लोग कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। इसके लिये लोग दुखी होते हैं तथा सहायता की मांग करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसे लोग अपने समुदाय तथा सरकार से न्याय की मांग करते हैं।

चुनाव में फिजूलखर्ची बंद हो

चुनाव में बाहुबल का प्रयोग और धन की बर्बादी पर लगाम कसने की दिशा में कठोरता से प्रयास की जरूरत है। आश्चर्यजनक यह है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का ट्रैड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह इसलिए खतरनाक है, क्योंकि रेस में दौड़ने वाले घोड़े पर दांव वही लगाता है जो सट्टेबाज होता है। जाहिर है बेहिसाब चंदा देने वाले पहले राजनीतिक दलों से अपने धंधे के नफा में होने की गारंटी ले लेते होंगे।

ग्रामीणों चुनावों में ग्रामवासी भाईचारे की भावना के तहत सारी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ का संचालन खुद कर, सरकार की फिजूलखर्ची रोक सकते हैं।

जिसके परिणाम स्वरूप सरपंच और सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे और चुनाव कराने की जरूरत नहीं रह जायेगी।

चुनाव के नाम पर अरबों रुपये पानी में बहने से रुक जाए तो सैकड़ों गरीबों को रोजगार मिल सकता है और विकास की रूप-रेखा तय हो सकती है।



निजीकरण का विरोध



- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो सरकारी बैंकों से ज्यादा भीड़ प्राइवेट बैंकों में होती!
- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो रोडवेज बस ज्यादा लोग प्राइवेट बस में चलना पसन्द करते!
- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो सरकारी अस्पताल से ज्यादा भीड़ प्राइवेट अस्पताल में होती!
- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो लाखों स्टूडेंट्स NEET_IITJEE की तैयारी न करते सीधे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते!
- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो लोग GOVT जॉब छोड़कर प्राइवेट जॉब करते!
- ◆ यदि निजीकरण अच्छा होता तो जवाहरनवोदयविद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा नहीं होता!
- ◆ निजीकरण के बाद क्या प्राइवेट कंपनी अपने किसी कर्मचारी को महंगाई बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ाएगी!
- ◆ क्या कोई प्राइवेट कंपनी वेतन सहित मेडिकल लीव देगी!
- ◆ क्या कोई प्राइवेट कंपनी हर साल वेतन वृद्धि करेगी!

- ◆ क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों को आपदा के समय वेतन देगी!
- ◆ क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने मृतक कर्मचारी के आश्रित को जॉब पर रखेगी!
- ◆ क्या कोई प्राइवेट कंपनी घाटे में जाने पर अपना व्यवसाय जारी रखेगी!
- ◆ ये निजीकरण नहीं देश को गुलामी की ओर धकेलना है!

आज बड़े बड़े भारतीय पूँजीपति देश के संसाधन खरीद सकते हैं लेकिन यदि ये संसाधन और घाटे में गए तो विदेशियों को बेच देंगे यही अंतिम सत्य है।

प्रकृति और कृषि, वन भूमि बचाओ

विदेशी कंपनियों के खाद बीज, कृषि रसायनों पर प्रतिबंध लगाकर देशी खाद बीज, कृषि रसायनों को प्रोत्साहन देना।

एचडी बीटी कपास, बीटी बैगन, जीएम सरसों आदि विदेशी कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है, इससे भविष्य में इन दवाई और बीज के परिणाम गंभीर आने वाले हैं किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इन विदेशी दवाई और बीज से किसानों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन दवाइयों व बीजों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए।

जल-साक्षरता

जल-साक्षरता जनसंख्या दबाव तथा आवश्यकतानुसार जल संसाधन का उचित उपयोग करने का योजनानुसार लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण एवं विकास वर्षा की बूँद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। जल का प्रधान एवं महत्वपूर्ण स्रोत मानसूनी वर्षा है। ऊपरी महानदी बेसिन में मानसूनी से वर्षा होती है। इस कारण वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता एवं असमान वितरण पाई जाती है। इस असमानता को दूर करने के लिये बेसिन में जल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है।

किसान की आत्महत्या का समाधान

- ◆ क्या केन्द्र और राज्य सरकारों को पता है कि किसान किस कारण से आत्महत्या करते हैं ?
- ◆ क्या देश में रोजाना लगभग ३९ किसान आत्महत्या करते हैं ?
- ◆ राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के कारणों को शामिल किया गया जाता है ,जैसे कृषि संकट, फसल नुकसान, कर्ज, परिवारिक समस्याएं और बीमारी आदि ?
- ◆ किसान आत्महत्या कर रहे हैं ये संख्या कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?
- ◆ किसान की आत्महत्या के बाद सरकार पीड़ित परिवार को क्या राहत राशि देती है ?
- ◆ सरकार बड़े उद्योगपति को ऋण माफ करती है तो क्या किसानों को सस्ते बीज और खाद नहीं दे सकती है ?

कोई भी मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाएगा, जब तक भारत पुनः विश्व गुरु नहीं बन जाता

एक विशालकाय मूर्ति पर इतना पैसा खर्च करने से अच्छा होगा यदि सूखा पीड़ित किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तैयार करने में धन का सदुपयोग हो इतनी बड़ी रकम अगर जरूरतमंदों को मदद के तौर पर दी जाती तो उनकी हालत काफी सुधर सकती थी

महिलाओं द्वारा जीवन साथी चुनने का अधिकार (स्वयंवर) को बढ़ावा

हमारी संस्कृति में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राधा-कृष्ण, गंगा-शांतनु, अर्जुन-उत्तूपी, भीम-हिंडम्बा, कृष्ण-सुभद्रा आदि कई उदाहरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं, जो प्रेम-भावनाओं का बखान करते हैं। हजारों वर्ष पहले भी महिलाओं को स्वयंवर के माध्यम से अपना जीवन-साथी चुनने की व्यवस्था हमारी परंपरा में रही है। प्रेमी-प्रेमिका की आपसी रजामंदी से गंधर्व-विवाह करने की आजादी थी, जिसके कई किस्से हमारी लोककथाओं में शामिल भी हैं।

शीर्ष अमीरों पर टेक्स बढ़ाया जाए

मान लीजिए सरकार चीनी पर कर लगाती है और चीनी के उत्पादकों से कर राशि प्राप्त करती है। इस प्रकार का मौद्रिक भार प्रत्यक्षतः चीनी के उत्पादकों पर पड़ता है। अब यदि उत्पादक कर का मौद्रिक भार किसी अन्य व्यक्ति पर (माना थोक विक्रेता पर) चीनी की कीमतों में वृद्धि करके डालता है और विवर्तन की यह प्रक्रिया थोक विक्रेता से अन्तिम उपभोक्ता तक जारी रहती है जो करापात उस उपभोक्ता पर पड़ेगा जो अन्तिम दशा में मौद्रिक भार उठायेगा। इसे परोक्ष मौद्रिक भार कहा जाता है।

फिन्डले शिराज के अनुसार, “कर भार की समस्या का विश्लेषण यह निर्धारित करता है कि कर का भुगतान कौन करता है अर्थात् कर का मौद्रिक भार किस पर पड़ता है।”

कर भुगतान में त्याग का तत्व भी सम्प्रिलित होता है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें कीमत देनी ही पड़ती है। परंतु करों के प्रकरण में कम से कम सैद्धान्तिक रूप में त्याग की भावना होती है, क्योंकि करदाता सावर्जनिक हित में कर देता है।

दारु की एक बोतल, पेट भर मुर्गा पर बिकने वाले मतदाता के लिए सीख



एक नेता वोट माँगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उनको 1000/- रुपये पकड़ाते हुए कहा, बाबाजी, इस बार वोट मुझे दें ।

बाबाजी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें वोट चाहिए तो एक गधा खरीद के लादो । नेता को वोट चाहिए था, वो गधा ढूँढ़ने निकला । मगर कहीं भी 20,000/- से कम कीमत पर कोई गधा नहीं मिला । तो वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला । कम से कम 20,000/- का एक गधा है । इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता पर 1000/- रुपये दे सकता हूँ ।

बाबाजी ने कहा, बेटा और शर्मिदा ना करों ।

तुम्हारी नजर में मेरी कीमत गधे से भी कम हैं । जब

गधा 20,000/- से कम में नहीं बिका तो मैं तो इंसान हूँ 1000/- में कैसे बिक सकता हूँ ?



जागो मतदाता जागो, अपनी कीमत पहचानो



- ❖ बच्चा-बच्चा करे पुकार, वोट डालना तुम्हारा अधिकार ।
- ❖ जन जन को चेताना है मतदाता को जागाना है ।
- ❖ जागो जागो हे मतदाता, तुम भारत के भाग्य विधाता ।
- ❖ घर-घर में सन्देश दो, वोट दो वोट दो ।
- ❖ जन-जन का है एक ही नारा, मतदान करना है अधिकार हमारा ।
- ❖ सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो ।
- ❖ न नशे से न नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से ।
- ❖ लोकतंत्र की है पहचान, मत, मतदाता और मतदान ।
- ❖ मत देना है अपना अधिकार, बदले में न ले कोई उपहार ।
- ❖ चाहे नर हो या हो नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी ।
- ❖ न जाति पे न धर्म पे, बटन दबेगा कर्म पे ।
- ❖ लालच देकर वोट जो मांगे, भ्रष्टाचार करेगा वो आगे ।
- ❖ बहकावे में कभी न आना, सोच समझकर बटन दबाना ।
- ❖ जागरुक देश की है पहचान, हो शत प्रतिशत मतदान ।
- ❖ जो करे राष्ट्र का उत्थान, उसी को करे मतदान ।
- ❖ वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बाराती ।
- ❖ आन, बान और शान से, सरकार बनाओ मतदान से ।
- ❖ अंतर्मन से देना वोट, बदले में नहीं लेना नोट ।